रहा है, कर्णाटक में खाते से हो रहा है, 1 करोड़ 8 लाख खाते खुल गए है, गरीबों को दान करेंगे सरज़जीन पर , भुगतान होगा बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते से । इस पर दृढ़ विचार कर 100 परसेंत भुगतान हम खाते से कराएंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Mr. Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, 1 would like to know from the hon. Minister (a) what is the mechanism adopted by the Government to gauge the performance of NREGA in various States; and (b) whether the Government has got any proposal to further assist the well performing States like Tamil Nadu.

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: महोदय, सारी जानकारियां ग्रामीण विकास की website पर उपलब्ध है और monthly progress report भी हम भेज रहे हैं। तमिलनाडु की हम प्रशांसा करते है, क्योंकि जो राज्य अच्छा काम करते हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं , उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर अधिकारी अच्छा काम करेंगे, तो उनको पुरस्कार देने का प्रावधान भी हमने किया है। ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Question 289. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I want to know whether further assistance will be extended. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question 289, please. ...*(Interruptions)*... Mr. Siva, it is over.

SHRI TIRUCHI SIVA: Wether further assistance will be extended... *(Interruptions)*...

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: और सहायता देंगे... जो अच्छा काम करेंगे, उनको खूब सहायता देंगे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण राजस्व की हानि

*289.**श्री मंगनी लाल मंडल**: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के कारण सरकार को प्रतिवर्ष एक लाख करोड रुपए से अधिक के राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है:

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के फलस्वरुप होने वाली राजस्व की हानि के संदर्भ में वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय के अभिमत और दृष्टिकोण में समरूपता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसका कारण और तत्स्बधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग़)और (घ) संसद में प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्रालय ने विशेष आर्थिक जोन से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो निम्नानुसार है;

> " विशेष आर्थिक जोनों से निर्यातों में निरंतर वृद्वि प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2005-2006 में एस ईजेडों द्वारा किए गए 22,840 करोड़ रुपये से निर्यात की तुलना में, 2006-07 में 34615 करोर रुपये के निर्यात किए गए है, जिनमें 52 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई है। वर्ष 2007-08 के लिए विशेष आर्थिक जोनों से 67088 करोड़ रुपये के निर्यात होने का अनुमान है।

उन एसईजेडों, जिन्हें एसईजेड अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित/ अधिसूचित किया गया है, मैं वर्तमान में 1277 इकाइंया प्रचालनरत है, जिनसे 2 लाख व्यक्तियों (जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं) को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हैं। इनमें से 36,463 व्यकित निजी राज्य सरकर के एस ईजेड में कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश फरवरी , 2006 के बाद स्थापित हुए थे। 10 फरवरी, 06 के बाद स्थापित नये अधिसूचित एस ईजेडों से 61015 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिला हैं।

एसईजेड अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले स्थापित 19 एस इजेडों में लगभग 7104 करोड़ रुपए का निजी निवेश किया गया है। 10 फरवरी, 2006 के बाद अस्तित्व में आए नये अधिसूचित एसईजेडों में 67,347 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही किया जा चुका है।

स्कीम के दुरुपयोग और एस ईजेडों मे मौजूदा उद्योगों की पुनर्स्थापना के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। तथापि अनुभव से यह पता चला है कि ये आशंकाएं निराधार है और विशेष आर्थिक जोनों में नये निवेश औंर रोजगार प्रवाहमान हैं। उदाहरणार्थ, श्री पेरूम्बुदूर स्थित नोकिया इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एसैइजेड पहले ही 6637 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। हैदराबाद स्थित रत्न एस ईजेड ने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के बाद 2000 व्यक्तियों को पहले ही नियोजित किया हैं जिनमें से 1200 लड़कियां है। उनका लगभग 30000 वयक्तियों को सीधे रोजगार देने का अनुमार है । आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे अपाचे एस ईजेड द्वारा प्रतिमाह, 10,00,000 जोदी जूतों के विनिर्माण हेतु लगभग 20,000 व्यक्तियों को नियोजित किए जाने कि संभावना है । आपचे एस ईजेड में इस समय 4,500 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। एक श्रीलंकाई एफडी आई परियोजना ब्राडिक्स अपेरेल्स से तीन वर्षो की अवधि के दौरान 60,000 कामगारों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। सेवा क्षेत्र में भी आईटी/ आईटीई एस एस ईजेड़ो में 12.5 मिलियन वर्ग मीटर के स्थान का सृजन किए जाने की संभावना है, जिनके फलस्वरूप 12.5 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। सृजित रोजगार के साथ एस ईजेड़ो में निवेश और अतिरिक्त अर्थिक कार्यकलाप के प्रभाव से प्राप्त लाभ एस ईजेड़ो को प्रदत्त कर संबंधी छूटों के कारण होने वाले राजस्व घाटे से काफी अधिक रहने का अनुमान है। ये एस ईजेट नव विकसित औद्योगिक बस्तियां है और उन्हें अन्यत्र से पुनः स्थापित नहीं किया जाता है।

एसईजेड़ों की स्थापना हेतु कृषि भूमि के अधिग्रहण के बारे में भी चितांए व्यक्त की गई है। केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि के अधिकग्रहण के मामले में पहली वरीयता बेकार और बंजर भूमि को दी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एस ईजेड़ो के लिए एक फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता हैं। यदि मजबुरीव्श विशेस रुप से बहु-उत्पाद विशेषः आर्तिक जोनो के लिए क्षेत्र संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु द्विफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण करना भी पड़े तो यह एस ईजेड़ हेतु कुल अपेक्षित भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों सहित देश में एसईजेडों की स्थापना से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया गया है। ईजीओएम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, सभी राज्य सरकारों को यह सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एस ईजेड़ का अनुमान नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने दिनांक 5 अप्रैल, 2007 के बाद उस एस ईजेड के लिए भूमि क अनिवार्य अधिग्रहण किया है अथवा करने का प्रस्ताव करती है। "

वाणिज्य विभाग के विचार उपर्युक्त तथ्यों से मेल खाते हैं। और इस प्रकार किसी मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता।

Revenue loss due to SEZs

†*289. SHRI MANGANI LAL MANDAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

whether it. is a fact that government is suffering loss of revenue worth more than one lakh crore rupees every year due to establishment of Special Economic Zones (SEZs);

if so, the details thereof and Government's point of view in this regard;

† Original notice of the question was received in Hindi.

whether it is also a fact that the ministry of Finance and Ministry of Commerce differ in their opinion and attitude with reference to loss of revenue as a result of setting up of SEZs; and

if so, the reasons thereof and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COMMERCE, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JAIRAM RAMESH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

No, Sir.

Does not arise.

and (d) In the Economic Survey for 2007-08 presented to the Parliament, the Ministry of Finance has given facts relating to Special Economic Zones which is as follows:

"Exports from Special Economic Zones have been showing steady increase. As compared to exports of Rs. 22,480 crore made by SEZs in 2005-06, exports to the tune of Rs. 34,615 crore have been effected in the year 2006-07, registering a growth of 52 per cent. Projected exports for 2007-08 from Special Economic Zones is Rs. 67088 crore.

In the SEZs which have been set up/notified prior to the coming into force of the SEZ Act, at present there are 1277 units in operation, providing direct employment to over 2 lakh persons (about 40 per cent of whom are women). Out of this, 36,463 persons are in the private/State Government SEZs, most of which had come up after February, 2006. The newly notified SEZs, which have come up after February 10, 2006, have provided direct employment to 61,015 persons.

Private investments in the 19 SEZs which were set up prior to coming into force of the SEZ Act 2005 is of the order of about Rs. 7104 crore. Investment of the order of Rs. 67,347 crore has already been made in the newly notified SEZs which came up after February 10, 2006.

Apprehensions have been expressed on misuse of the scheme and relocation of existing industries into SEZs. However, experience, has shown that these apprehensions are ill founded and fresh investments and employment have been flowing into the Special Economic Zones. For example, Nokia Electronics hardware SEZ in Sriperumbudur is already providing employment to 6637 persons, majority of whom are women. Hyderabad Gems SEZ has already employed 2000 persons after providing training to them, out of which 1200 are girls. They have projected direct employment of about 30,000 persons. Apache SEZ being set up in Andhra Pradesh, is expected to employ 20,000 persons to manufacture 10,00,000 pairs of shoes every month. Current employment in Apache SEZ is 4500 persons. Brandix Apparels, a Sir Lankan FDI project is expected to provide employment to 60,000 workers over a period of three years. Even in the services sector 12.5 million sq. metres space is expected to be created in the 1T/ITES SEZs which is estimated to translate into 12.5 lakh jobs. The benefits derived from multiplier effect of the investments and additional economic activity in the SEZs along with the employment generated is estimated to far outweigh the revenue losses on account of tax exemptions

given to the SEZs. These SEZs are freshly developed industrial clusters and are not relocated from elsewhere.

Concerns have been expressed regarding acquisition of agricultural land for setting up SEZs. The State Governments have been advised by the Centre that in case of land acquisition for Special Economic Zones, first priority should be for acquisition of waste and barren land and if necessary single crop agricultural land could be acquired for the SEZs. If perforce a portion of double cropped agricultural land has to be acquired to meet the minimum area requirements, especially for multi product Special Economic Zones, the same should not exceed 10 per cent of the total land required for the SEZ. Various issues related to setting up of SEZs in the country, including issues raised by various political parties, have been addressed by the Empowered Group of Ministers (EGOM). Pursuant to the decision taken by the EGOM, all State Governments have been informed that the Board of Approval will not approve any SEZs where the State Governments have carried out or propose to carry out compulsory acquisiton of land for such SEZs after April 5, 2007."

The views of the Department of Commerce are in agreement with the above facts and hence the question of any difference of opinion does not arise.

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, मैंने जो प्रश्न पूछा है और सरकार द्वारा जो उत्तर सभा पटल पर रखा गया है, दोनों में तालमेल नहीं है। उत्तर बहुत ही असंतोषजनक है। मैंने सिर्फ पूछा है कि जो एस0ई0जेड0 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हुई है, उस मामले में राजस्व की जो क्षति हो रही है, तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है, दोनों में विरोधाभास है। दोनों में अंतर्विरोध है आर मैंने इसी के संबंध में पूछा है, लेकिन उन्होने जो उत्तर दिया है, वह दिया भू अर्जन से संबंधित, निर्यात से संबंधित और रोज़गार से संबंधित। महोदय, उत्तर तो संतोषजनक नहीं हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए लेकिन फिर मैं पूछता हूं, अपने प्रशन का उत्तर दोहराता हूं कि इस विषय पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामले में बराबर समाचार-पत्रों में खबरे छपती रहती हैं कि क्या यह बात सही है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से राजस्व की भारी क्षति हुई है, ऐसा वित्त मंत्रालय का मामना है? यह मेरा पहले नंबर का प्रश्न है और दूसरा यह कि इस तैयार करने के मामले में वित्त मंत्रालय से वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सहमति नहीं ली है, सम्पर्क नहीं किया है और को ऑर्डिनेशन नहीं किया है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Isn't Question Hour over, Sir?

MR. CHAIRMAN: Not yet. Not yet. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir it is true that there are differing perceptions on the methodology that is used to calculate the notional revenue loss, and I want to underline the word "notional revenue loss". There are substantial revenue gains as well. A comprehensive cost-benefit analysis of the SEZs can happen only after SEZs become operational. All such calculations, before SEZs become operational, are purely theoretical and hypothetical.

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, माननीय मंत्री ने काल्पनिक notional revenue loss की बात की है । काल्पनिक राजस्व क्षति की बात की है, मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके यह जो notional revenue loss है, इस मामले में कोई calculation किया है, मूल्यांकन किया है कि कितनी क्षति है और उस क्षति की भरपाई कैसे होगी?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the priority now is not to do calculations, but to make SEZs operational ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shri Sharad Yadav. ...*(Interruptions)*... Shri Sharad Yadav. ... *(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: The Minister is not answering the questions, Sir. ...*(Interruptions)*... He is not answering the questions.

...*(Interruptions)*...

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, मेरा जो पूरक हैं, उसका पूरा उत्तर उन्होंने नहीं दिया।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ चुके है। ....(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल: सरकार ने मूल उत्तर से , सप्लीमेटरी से गुमराह किया है। ....(**व्यवधान**)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he cannot answer the questions. ...*(Interruptions)*... He is not answering. Sir, this is very unfair.

...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: महोदय, जो सवाल पूछा गया था, आपने चतुराई से टाला है।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over. I am afraid so!

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Secretive purchase of land along Pakistan border in Rajasthan

†*203. SHRI AJAY MAROO:
SHRI RUDRA NARAYAN PANY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

whether Government's attention has been drawn to media reports in which it has been mentioned that the land of certain areas of Rajasthan along Pakistan border has been purchased by some unknown persons in a secretive manner;

if so, the information available with Government in this regard; and

the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI V. RADHIKA SELVI) (a) to (c) Government is aware that large scale land transactions over the last five years have taken place in the border areas of Rajasthan. The State Government of Rajasthan have informed that they have initiated a detailed enquiry into these transactions with the intention of identifying the purchasers and ascertaining the motives behind such transactions. Preliminary enquiries indicate that lands have also been purchased by many parties from places other than Rajasthan. While speculation linked to expectations about improved highway connectivity, new projects of irrigation and prospects of oil and gas finds may be a factor for accelerated investment in land in these areas, a definite conclusion/ analysis will be possible only after completion of the detailed enquiry being undertaken by the Government of Rajasthan with the support of the Central Government agencies. A high level review on the subject matter has also been held in the Ministry of Home affairs and the issue is being closely monitored in coordination with the State Government, from time to time.

† Original notice of the question was received in Hindi